सरकार का प्रयास : विकास बने जनांदोलन

राजीव आहूजा

वास्तव में सुधारों/कार्यक्रमों की सूची काफी लंबी है। सरकार ने प्रमुख तौर पर लोक-लुभावन वादों से परहेज किया है। उसने वैसे लोक-लुभावन वादों का सहारा नहीं लिया है, जिससे विकास की उपेक्षा होती है। समाज के तकरीबन सभी तबकों, सभी आयु वर्गों और बाकी क्षेत्रों के लिए सुधार/कार्यक्रम हैं। ऐसा करते हुए वह विकास और राजनीति के बीच घालमेल को काफी कम करने में सफल रही है

केंद्र सरकार ने हाल में कहा है कि उसके एजेंडे के तीन अहम पहलू हैं- विकास, तेज विकास और सर्वांगीण विकास। सूत्रों के मुताबिक, एक और संदर्भ में सरकार ने यह भी कहा है कि विकास को जन आंदोलन बनाना मौजूदा वक्त की जरूरत है।

इस बात को लेकर काफी कम लोग असहमत होंगे कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने जिस तरह से विकास को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है, वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के मकसद से मौजूदा सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा बैंक योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत आदि शामिल हैं, कार्यक्रमों की सूची यहीं पर नहीं ठहरती, इसकी सूची काफी लंबी है। मोदी सरकार द्वारा पिछले 4 साल में शुरू किए गए कई कार्यक्रमों के बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है?

एक आसान तरीका विभिन्न सुधारों/कार्यक्रमों को आर्थिक वृद्धि और बदलाव के औजार की तरह देखने का है। हालांकि, इसके लिए गुंजाइश सीमित है, लेकिन यह तरीका उपयोगी नजरिया प्रदान करता है।

इस नजरिये के हिसाब से कोई इन सुधारों/कार्यक्रमों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांट सकता है: (1) वैसे कार्यक्रम जिनसे तुरंत लाभ हुआ है (2) वैसी योजनाएं, जिनसे लंबी से मध्यम अवधि में फायदा होने की बात की गई है और (3) वे कार्यक्रम जिन पर छोटी अवधि में लागत लगाने से बाद में अहम लाभ हो सकता है। 'तुरंत लाभ' वाली योजनाओं में देश में डॉक्टरों की कमी की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के सभी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से गैर-जंगली इलाकों में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे भारतीय वन अधिनियम की सूची से हटाने जैसे मामले शामिल हैं। जिन कदमों से मध्यम से लंबी अवधि में फायदा होगा, उनमें देश के अलग-अलग राज्यों/हिस्सों में एम्स जैसे नए अस्पताल खोलना, बुलेट ट्रेन की शुरुआत आदि हैं। इसी तरह, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और बड़े नोटों के विमुद्रीकरण जैसे ढांचागत सुधार आदि ऐसे सुधार के उदारहण हैं, जिनसे कुछ समय के लिए दिक्कत हुई, लेकिन बाद में इससे जबरदस्त फायदा होने की संभावना है।

आर्थिक जानकारों की राय

इस संबंध में एक और उपयोगी नजरिया सरकार के विभिन्न आर्थिक सुधारों/कार्यक्रमों को अर्थशास्त्रियों के चश्मे से देखने का हो सकता है: वैसे सुधार/कार्यक्रम जो बाजार की असफलता से निपटते हैं या निपटेंगे और वे जो सरकार की नाकामी को दुरुस्त कर रहे हैं या करेंगे। बाजार की अर्थव्यवस्था के बड़े-बड़े पैराकार भी मानते हैं कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है, जब बाजार का तंत्र धराशायी हो जाता है। ऐसे में सरकारी हस्तक्षेप मुहैया कराने की जरूरत होती है। चाहे सार्वजनिक हित के लिए प्रावधान की बात हो, या कंपनियों की उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने का मामला, जिसके तहत वे बाजार में अपनी

लेखक विकास अर्थशास्त्री हैं और उन्हें डेवलपमेंट सेक्टर में 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। उनकी हालिया नौकरी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) में थी। वे यूएनडीपी, आईएलओ, डीएफआईडी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में सलाहकार की भूमिका भी निभा चुके हैं। ईमेल: ahujaahuja@yahoo.com.

दबदबे की स्थिति का बेजा फायदा उठाती हैं, सरकार की नजर जरूरी है। साथ ही, मैक्रो-आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा या कम मांग के कारण बाजार 'नहीं होने' या कुछ अन्य परिस्थितियों में भी यह जरूरी है।

बाजार की असफलता से निपटना

मौजूदा सरकार अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को तेजी से बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार न सिर्फ नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि उसने पिछली सरकारों के दौर में अटकी हुई परियोजनाओं को भी शुरू किया है। यह इस हिसाब से सार्थक है कि यह सार्वजनिक हित के मद्देनजर बाजार की असफलता जैसी चुनौती से निपटता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य होने के नाते मौजूदा सरकार ने वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हितों को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

चाहे डिजिटल सौदों को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने की बात हो या राष्ट्रीय पोषण मिशन पर नए सिरे से जोर देने का मामला या स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, इन तमाम

अभियानों का मकसद सकारात्मक नतीजा हासिल करना है यानी ऐसी हर पहल विकास की प्रक्रिया से जुड़ी रहे। इसी तरह, गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के मकसद से भारत स्टेज उत्सर्जन मानक को IV से बढ़ाकर VI करना हो या ऑक्सिटोसिन की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात, इन कवायदों का मकसद नकारात्मक असर को कम करना है।

केंद्र सरकार वित्तीय समावेशन के मकसद से जन धन योजना पेश कर, गरीबों को सस्ते में घर देने के मकसद से सभी के लिए घर योजना की शुरुआत कर, कौशल भारत अभियान आदि के जरिये 'गैर-मौजूद' बाजारों के लिए गुंजाइश बना रही है। कौशल विकास अभियान का मकसद वोकेशनल और तकनीकी प्रशिक्षण मुहैया कराना है। मैक्रो-आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादन और उत्पादकता पर जोर देने के मकसद से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना आदि शामिल हैं। इसी तरह, छोटे उद्योमियों/नवोन्मेष में जुटे लोगों व इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए आसानी वित्तीय इंतजाम पर भी काम किया जा रहा है। मसलन मुद्रा योजना के अलावा स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने खुद के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है: 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना, अगले तीन साल में विदेशी सैलानियों की आवक में दोगुनी बढ़ोतरी करना, 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावॉट बिजली पैदा करने का लक्ष्य आदि। आर्थिक वृद्धि पर फोकस वाले क्षेत्रों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मोदी सरकार न सिर्फ विकास के माध्यमों व साधनों को विविधता का स्वरूप देने

की कोशिश कर रही है, बल्कि समाज के सभी तबके से लोगों की संभावनाओं को खोलकर विकास को लोकतांत्रिक स्वरूप भी दे रही है।

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर (बीपीएल) करने वाले परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। इसी तरह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मकसद गरीब परिवारों को बीमारी के दौरान अस्पताल के खर्च से मुक्ति दिलाना है।

बाजार की असफलताओं के अलावा सरकार की असफलताएं भी हो सकती हैं। मुमकिन है कि सरकार बाजार की असफलताओं को दुरुस्त करने और गरीबी कम करने और समानता को बढ़ावा देने जैसे अपने प्रमुख कार्यों के निर्वहण में नाकाम हो जाए।

सरकारी असफलताओं को दुरुस्त करना

बाजार की अर्थव्यवस्था में किसी भी सरकार का एक अहम काम मानक तय करना और नियमन विकसित करना होता होता है, ताकि बाजार का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। सरकार ने नई नियामक इकाइयों के गठन के लिए नए प्रावधान किए हैं। इसके अलावा मौजूदा नियामकों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर सरकार ने रियल एस्टेट सौदों को ज्यादा पारदर्शी बनाने और घर के खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए रियल एस्टेट अधिनियम पास किया है। इसी तरह, सरकार भारत में खाद्य सुरक्षा नियमों को मजबूत बना रही है, बैंकिंग नियमों का सख्त बना रही हैं। पेशेवर मापदंडों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मेडिकल डॉक्टरों की पेशेवर इकाइयों, लेखापालों, ऑडिटरों आदि की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार नियामक संबंधी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के नियामक के अभाव में दवाओं और मेडिकल उपकरण उद्योग में बड़े पैमाने पर बाजार की असफलता सामने आई है और यहां कमीशनों और हेराफेरी का बोलबाला है। अब यह मसला सरकार की निगाह में हैं और इसे दुरुस्त करने की शुरुआत हो चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए सरकार ने विनिवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है। सरकार बदलते आर्थिक माहौल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रासंगिक बने रहने के लिए इन इकाइयों को खुद से बदलाव करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसकी एक मिसाल इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैं, जो डाक विभाग के 1.5 लाख डाकघरों को सहारा देगा। इसके अलावा, सरकार इन प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में कम से कम राजनीतिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।

अपने 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' अर्थात् 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' पहल के तहत सरकार मानवीय इंटरफेस की जगह डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है, ताकि लोगों को बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और लोगों का जीवन आसान हो सके। इस पहले के लिए जरिये कारोबार और उद्यम के फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाना और समानता को भी बढ़ावा देने की कोशिश है।

समानता को बढ़ावा

समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक निश्चित इलाके या तय आबादी समूह को ध्यान में रखते हुए कई तरह के अभियान चलाए हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास पर खास जोर दिया है। यह क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र के देश के बाकी हिस्सों की तरह विकास के लिए उत्तर-पूर्व इलाके में विकास की कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसी तरह, सरकार ने 100 से भी ज्यादा एस्पाइरेशनल यानी 'संभावनाशील' जिलों की पहचान की है, जो विकास के कुछ अहम सूचकांकों के लिहाज से पिछड़े हुए हैं। 'संभावनाशील जिलों का कायाकल्प कार्यक्रम' के तहत सरकार इन जिलों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए खास ध्यान दे रही है। इसी

तरह, मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के 1,000 दिनों के भीतर 100 फीसदी गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की मुख्य वजह सरकार का एकसमान विकास का एजेंडा है। इस पहल को एक और स्कीम से जोड़ा जा रहा है, जिसका मकसद हर घर में बिजली पहुंचाना है।

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर (बीपीएल) करने वाले परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। इसी तरह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मकसद गरीब परिवारों को बीमारी के दौरान अस्पताल के खर्च से मुक्ति दिलाना है। ये योजनाएं उन कार्यक्रमों की बानगी हैं, जो एक खास आबादी समूह के बीच समानता को बढ़ावा देती हैं। सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और लीकेज रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं में नकद इंसेंटिव/नकदी ट्रांसफर का सिस्टम लाया जा रहा है यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत रकम सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।

एक और आधार

बाजार की असफलताओं से निपटने और समानता हासिल करने के मकसद के अलावा सरकारी हस्तक्षेप का एक और आधार व्यवहारवादी अर्थशास्त्र से मिला है, जिसमें लोगों के व्यवहार और पसंद को प्रभावित करने में सरकार की भूमिका को सही बताया जाता है। वास्तव में सरकार कई क्षेत्रों में सामाजिक संदेशों के जरिये प्रक्रियाओं, व्यवहार और पंसद को लेकर लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मसलन बेटियों को लेकर जागरूकता फैलाने और गांवों को खुले शौचालय की आदत से मुक्त करने में ऐसा किया जा रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने से कभी परहेज नहीं किया है और इन लक्ष्यों को हासिल करने में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मिसाल के तौर पर सेहमतंद बने रहने के लिए लोगों से योग करने का अनुरोध, खादी कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह, वैसे लोगों के लिए गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब को अपनाने की गुजारिश आदि।

विकास को अच्छी राजनीति में बदलना

ऊपर पेश किए उदारहण महज बानगी हैं। वास्तव में सुधारों/कार्यक्रमों की सूची काफी लंबी है। सुधारों/कार्यक्रमों के पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि सरकार ने प्रमुख तौर पर लोक-लुभावन वादों से परहेज किया है। उसने वैसे लोक-लुभावन वादों का सहारा नहीं लिया है, जिससे विकास की उपेक्षा होती है।

समाज के तकरीबन सभी तबकों, सभी आयु वर्गों और बाकी क्षेत्रों के लिए सुधार/कार्यक्रम हैं। ऐसा करते हुए वह विकास और राजनीति के बीच घालमेल को काफी कम करने में सफल रही है।

लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं के मुकाबले विकास की भारी कमी वाले इस देश में कई और क्षेत्रों में सरकार का ध्यान आकर्षित करने की खातिर होड़ है। सरकार एक ही वक्त में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। सरकार की दिशा सही है। हालांकि, सुधारों या कार्यक्रमों के लागू होने की रफ्तार कई मामलों की सक्रियता पर निर्भर करती है। मसलन सरकारी इकाइयों के बीच समन्वय, सुधारों को नाकाम करने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा पेश की गई चुनौतियां। ❑